(Rs. in lakh)

State	Year	
	1993-94	1994-95 (upto Dec.' 94)
Andhra Pradesh	15.13	71.53
Bihar	9.45	7.24
Orissa	77.36	47 22
Uttar Pradesh	30.87	5 64
West Bengal	21.02	42.48

बिहार में अकालग्रस्त और अभावग्रस्त जिले

4875. **श्री आस मोहम्मद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अकालग्रस्त तथा अभावग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित जिले कौन-कौन से हैं; और

(ख) इन क्षेत्रों में किए गए राहत कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में कोई भी क्षेत्र सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोग प्रवण विदेशी संकर/नस्लें

4876. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी/संकर नस्लों में जल्दी बीमारियां लगती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) ये जानवर उन देशों से होते हैं जहां भारत के पशुओं में पाए जाने वाले रोग नहीं होते। मूल देशों में न पाए जाने तथा उनकी आनुवंशिक बनावट ने उनमें इन रोगों को सहन करने की शक्ति नहीं होती ।

(ग) भारत में खुरपका तथा मुहंपका रोग पशुप्लेग, ब्लेक क्वार्टर, रक्तस्रावी पूतिरक्तता आदि जैसे प्रमुख रोगों से विदेशी/वण संकर पशुओं की रक्षा करने के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल का कार्यक्रम चल रहा है। देश पर्याप्त मात्रा में टीकों का उत्पादन भी कर रहा है जो फार्म स्तर पर प्रयोग के लिए उपलब्ध है ।

Impact of new Economic Policy on Agriculture

4877. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to the news-item appearing in Jansatta of 23rd February, 1995 regarding impact of New Economic Policy on Agriculture; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) The news-item appearing in Jansatta of 23rd February, 1995 has been seen. The agriculture sector in the country has also been influenced by the New Economic Policy. The major areas of economic reforms in agriculture sector relate to reversal of trends of investment, maintenance of remunerative prices, encourasing processing of agricultural produce in rural areas, phasing out of domestic trade and marketing restrictions, promotion of external trade and scaling down of preferential protection to the industrial sector. Appropriate action on these lines has already been initiated. Public Sector outlays for agriculture and allied sectors have already been raised substantially in the Eighth Plan.

Revitalisation of cooperative sector

4878. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps recently to revitalise the cooperative sector; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) The Central Government have recently initiated a series of measures to revitalise cooperatives at the grass root level. These include:

(i) Initiating the process of Business Development Planning in Primary Agricultural Cooperative Societies;

(ii) Strengthening the role of Federal Cooperatives in relation to Primary Cooperative Societies;

(iii) Supporting of self-help efforts of the Cooperatives;

(iv) Efforts to make Cooperative Sector democratic and functionally independent;

(v) Strengthening of training of cooperative personnel to make the cooperatives professionalised and improve their working.

राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण बोर्ड

4879. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गन्ने का वाजिब मूल्य तय करने के लिए बनाई गई केन्द्रीय समिति ने राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण बोर्ड बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव को मानने के लिए तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सरकार ने 31.3.1994 को राज्य द्वारा सूचित गन्ने के मूल्यों की मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में की जाने वाली सिफारिशें करने के लिए 5 राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की है । समिति ने गन्ने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण बोर्ड के गठन की सिफारिश की है ।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशों को विचार-विमर्श हेतु 6.5.1995 को होने वाले सभी गन्ना उत्पादक राज्यों के चीनी मंत्रियों के सम्मेलन में रखा जा रहा है ।

Increase in the Proudction of Pulses

4880. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to Economic Survey report the production of pulses has increased from 127 lakh tonnes in 1960-61 to 131 lakh tonnes in 1993-94.